

## क्षेत्रीय आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में एमएसएमई: झारखंड का अध्ययन

धर्मेन्द्र कुमार \*<sup>1</sup>

शोधार्थी, वाणिज्य विभाग,  
सोना देवी विश्वविद्यालय, घाटशिला, जमशेदपुर, झारखंड

डॉ. पूजा कुमारी <sup>2</sup>

वाणिज्य विभाग,  
सोना देवी विश्वविद्यालय, घाटशिला, जमशेदपुर, झारखंड

\* *संवाददाता: धर्मेन्द्र कुमार, dharmendrasinghmdg@gmail.com*

### एब्सटैक्ट:

झारखंड के रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (MSMEs) का अहम रोल है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, लेकिन यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ एक जैसी नहीं है। यह पेपर रीजनल डेवलपमेंट में MSMEs के योगदान की जाँच करता है। इसके लिए उनके ऑपरेशन के स्केल, रोज़गार पैदा करने, सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका का एनालिसिस किया गया है। यह स्टडी MSME मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, उद्यम रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज (UAP) डैशबोर्ड से मिले सेकेंडरी डेटा पर आधारित है। नतीजों से पता चलता है कि MSMEs पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं, और कुल यूनिट्स में माइक्रो एंटरप्राइज का बड़ा हिस्सा है। यह सेक्टर खास तौर पर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में खेती के अलावा काफी रोज़गार पैदा करता है, जिससे बेरोज़गारी और माइग्रेशन कम होता है। MSMEs ट्रेडिशनल माइनिंग-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ से आगे बढ़कर ट्रेड, मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में एक्टिविटीज़ को बढ़ाकर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में भी योगदान देते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के ज़रिए फॉर्मलाइज़ेशन बढ़ने से क्रेडिट, सरकारी स्कीम और मार्केट के मौकों तक पहुँच बेहतर हुई है। हालाँकि, कम इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस तक सीमित पहुँच, स्किल की कमी और धीमी एंटरप्राइज ग्रोथ जैसी चुनौतियाँ MSMEs के पूरे पोटेण्शियल को रोकती रहती हैं। पेपर का निष्कर्ष है कि झारखंड में संतुलित और टिकाऊ क्षेत्रीय आर्थिक विकास पाने के लिए टारगेटेड पॉलिसी सपोर्ट के ज़रिए MSME इकोसिस्टम को मज़बूत करना ज़रूरी है।

**कीवर्ड:** MSMEs, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन, झारखंड.

## 1. परिचय

झारखंड में इलाके के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) अहम भूमिका निभाते हैं, जहाँ पारंपरिक रूप से आर्थिक विकास मिनरल-बेस्ड बड़े उद्योगों पर निर्भर रहा है। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, राज्य को असमान औद्योगिक विकास, बेरोज़गारी और ग्रामीण-शहरी असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में, MSMEs रोज़गार पैदा करके, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर और शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोकल वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देकर सबको साथ लेकर चलने वाले विकास में अहम योगदान देते हैं (पांडे एट अल., 2024; कुमार, 2023)। MSME मंत्रालय के अनुसार, दिसंबर 2024 तक झारखंड में लगभग 11.81 लाख रजिस्टर्ड MSMEs थे, जबकि MSME डैशबोर्ड (उद्यम और इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज) ने लगभग 14.69 लाख यूनिट्स की रिपोर्ट दी, जो एक मज़बूत और भौगोलिक रूप से फैले हुए औद्योगिक आधार को दिखाता है। यह बड़ा फैलाव MSMEs को ज़िला-लेवल के आर्थिक विकास और रोज़ी-रोटी कमाने के लिए ज़रूरी बनाता है (MSME मंत्रालय, 2024)। झारखंड में MSMEs खास तौर पर इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उनमें मेहनत लगती है, जिससे खेती के अलावा दूसरे रोज़गार मिलते हैं और ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से माइग्रेशन कम होता है (NITI आयोग, 2023)। इसके अलावा, MSMEs माइनिंग और स्टील क्लस्टर के आस-पास के सहायक उद्योगों को सपोर्ट करके और लोकल सप्लाय चैन को मज़बूत करके आर्थिक डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देते हैं (गुप्ता, 2025)। इसलिए, MSMEs झारखंड में इनकम बढ़ाने, आर्थिक मज़बूती में सुधार करने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करके टिकाऊ और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए एक अहम ज़रिया हैं।

## 2. साहित्य समीक्षा

लेखक और वर्ष	अध्ययन का उद्देश्य	कार्यप्रणाली/दृष्टिकोण	मुख्य निष्कर्ष	वर्तमान अध्ययन से प्रासंगिकता
गुप्ता (2025)	झारखंड के इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ पैटर्न और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसकी भूमिका की जांच की गई।	वर्णनात्मक सांख्यिकी का उपयोग करते हुए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) से माध्यमिक डेटा।	मिनरल रिसोर्स के बावजूद इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक जैसी नहीं थी। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पॉलिसी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है।	झारखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और MSME ग्रोथ पर असर डालने वाली चुनौतियों पर बैकग्राउंड बताता है।
कुमार (2025)	रांची, झारखंड में MSME कर्मचारियों के बीच जॉब सैटिस्फैक्शन की जांच की गई।	150 MSME कर्मचारियों के केश्वनेयर का इस्तेमाल करके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।	एम्प्लॉई वर्कप्लेस रिलेशन और जॉब सिक्योरिटी से खुश थे। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतर HR प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत थी।	झारखंड में MSME परफॉर्मेंस पर असर डालने वाले ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर्स पर रोशनी डाली गई।

पांडे एट अल. (2024)	भारत में रोज़गार, GDP, एक्सपोर्ट और FDI में MSME के योगदान का एनालिसिस किया गया।	कोरिलेशन और रिग्रेशन का इस्तेमाल करके सेकेंडरी डेटा एनालिसिस।	MSMEs ने रोज़गार और आर्थिक विकास में अहम योगदान दिया। सरकारी योजनाओं ने MSME के विस्तार में मदद की।	रीजनल डेवलपमेंट स्टडीज़ को सपोर्ट करने वाले MSMEs के मैक्रोइकोनॉमिक महत्व को दिखाता है।
कलैसेलवी एट अल. (2024)	भारत के आर्थिक विकास में SMEs की भूमिका की जांच की गई।	SME सेक्टर का एनालिटिकल रिव्यू।	SMEs ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स में 90% से ज़्यादा का योगदान दिया और रोज़गार, इनोवेशन और एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया।	संतुलित क्षेत्रीय विकास में SMEs के महत्व का समर्थन करता है।
अहमद एट अल. (2023)	झारखंड के संदर्भ में भारत में ग्रामीण आर्थिक विकास में MSMEs की भूमिका का अध्ययन किया।	सेकेंडरी डेटा और पॉलिसी एनालिसिस।	MSMEs ने सरकारी कोशिशों से मदद लेकर एंटरप्रेन्योरशिप, रोज़गार और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा दिया।	झारखंड में MSME डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बैकग्राउंड देता है।
कुमार जी. (2023)	भारत में इनक्लूसिव ग्रोथ के ड्राइवर के तौर पर MSMEs की जांच की गई।	सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करके एनालिटिकल स्टडी।	MSMEs ने क्षेत्रीय भेदभाव को कम किया और पिछड़े ग्रुप्स के बीच रोज़गार को बढ़ावा दिया।	समावेशी क्षेत्रीय विकास के साधन के रूप में MSMEs को सपोर्ट करता है।
कडाबा एट अल. (2022)	MSME डेवलपमेंट में PMMY (MUDRA स्कीम) की भूमिका की स्टडी की।	सरकारी रिपोर्ट से सेकेंडरी डेटा।	MUDRA लोन ने एंटरप्रेन्योरशिप और रोज़गार को सपोर्ट किया लेकिन अवेयरनेस में सुधार की ज़रूरत थी।	MSME ग्रोथ पर असर डालने वाले फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म को दिखाता है।
गुप्ता (2022)	भारत में छोटे उद्योगों पर Covid-19 के असर का एनालिसिस किया गया।	सेकेंडरी डेटा और पॉलिसी एनालिसिस।	पेमेंट में देरी और सप्लाय में रुकावटों से MSMEs पर असर पड़ा। TReDS ने फाइनेंशियल एक्सेस को बेहतर बनाया।	MSME सस्टेनेबिलिटी पर असर डालने वाली चुनौतियों के बारे में बताता है।
मजीद एट अल. (2021)	MSME इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में R&D की भूमिका की स्टडी की।	उद्योग डेटा के वार्षिक सर्वेक्षण का विश्लेषण (2016-2018)।	MSMEs में R&D का लेवल कम और एक जैसा नहीं था। इनोवेशन के लिए पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत थी।	MSME ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के महत्व का समर्थन करता है।

सरकार (2021)	भारत में रोज़गार पैदा करने में MSME की भूमिका की जांच की गई।	सेकेंडरी डेटा एनालिसिस।	MSMEs ने रोज़गार पैदा किया लेकिन क्षेत्रीय अंतर मौजूद थे।	MSMEs के सामाजिक-आर्थिक महत्व का सबूत देता है।
ग्रैंडी (2019)	क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और गरीबी कम करने की जांच की।	केस स्टडी अप्रोच और पॉलिसी एनालिसिस।	क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए लोकल अडैप्टेशन और लंबे समय तक चलने वाले इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी।	क्लस्टर-बेस्ड MSME डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है।
हुसैन (2019)	भारत में SME एक्सपोर्ट के रीजनल कारणों की स्टडी की।	रीजनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके एम्पिरिकल एनालिसिस।	स्किल्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस ने SME एक्सपोर्ट पर असर डाला।	MSMEs पर असर डालने वाले रीजनल डेवलपमेंट फैक्टर्स को सपोर्ट करता है।
जेना एट अल. (2018)	भारतीय राज्यों में MSME मैनुफैक्चरिंग परफॉर्मेंस की जांच की गई।	एमएसएमई विनिर्माण व्यवसाय सुविधा सूचकांक।	इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी में अंतर के कारण MSME का परफॉर्मेंस अलग-अलग रहा।	राज्य-स्तरीय MSME विकास विश्लेषण में सहायता करता है।
रजक एट अल. (2018)	झारखंड में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और MSME डेवलपमेंट की पढ़ाई की।	सेकेंडरी डेटा और पॉलिसी एनालिसिस।	झारखंड का इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बढ़ रहा था लेकिन इसके लिए पॉलिसी सपोर्ट और फाइनेंस की ज़रूरत थी।	झारखंड में MSME ग्रोथ के लिए रीजनल बैकग्राउंड देता है।

### 3. द्वितीयक डेटा का विश्लेषण

झारखंड में MSME सेक्टर, इलाके की आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा और तेज़ी से बढ़ने वाला बेस है, जिसमें लगभग 11-15 लाख बिज़नेस अलग-अलग ज़िलों में फैले हुए हैं। कुल MSME में माइक्रो एंटरप्राइज़ का हिस्सा लगभग 99% है, जो छोटे पैमाने की और मेहनत वाली आर्थिक गतिविधियों का दबदबा दिखाता है, जो ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में रोज़गार पैदा करने में मदद करती हैं। छोटे और मीडियम एंटरप्राइज़ का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन वे टेक्नोलॉजी में तरक्की और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में योगदान देते हैं। अनुमान है कि इस सेक्टर से लगभग 30-35 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो खेती-बाड़ी से इतर रोज़गार का लगभग 40-45% है, जिससे बेरोज़गारी और माइग्रेशन कम करने में यह अहम भूमिका निभाता है।

सेक्टर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है कि ट्रेड (लगभग 38%) सबसे ज़्यादा है, इसके बाद मैनुफैक्चरिंग (32%) और सर्विसेज़ (30%) हैं, जो मिनरल-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अलावा इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है। MSMEs राज्य के GSVA में लगभग 25-30% का योगदान देते हैं, जिससे इनकम जेनरेशन और लोकल कंजमप्शन को सपोर्ट मिलता है। ग्रामीण और आदिवासी ज़िलों में अच्छी-खासी मौजूदगी इनक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देती है, जबकि 20-25% महिलाओं के मालिकाना हक वाले एंटरप्राइज़

महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में योगदान देते हैं। उद्यम के तहत लगभग 7.4 लाख फॉर्मलाइज़्ड यूनिट्स और UAP के तहत 7.2 लाख इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज़ बढ़ते फॉर्मलाइज़ेशन और क्रेडिट और सरकारी स्कीमों तक बेहतर एक्सेस का संकेत देते हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे बड़े क्लस्टर लोकल वैल्यू चेन और रीजनल इकोनॉमिक रेजिलिएंस को मज़बूत करते हैं।

#### 4. निष्कर्ष

स्टडी से पता चलता है कि झारखंड के रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में MSMEs बहुत ज़रूरी रोल निभाते हैं। लगभग 11-15 लाख एंटरप्राइज़ के साथ, MSMEs राज्य में सबसे बड़ा इकोनॉमिक बेस बनाते हैं। इनमें से ज्यादातर एंटरप्राइज़ माइक्रो यूनिट (लगभग 99%) हैं, जिससे पता चलता है कि इस सेक्टर में मुख्य रूप से छोटे और लेबर-बेस्ड बिज़नेस हैं जो ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में फैले हुए हैं। MSMEs लगभग 30-35 लाख लोगों को नॉन-फार्म रोज़गार देते हैं, खासकर ग्रामीण, आदिवासी और सेमी-स्किल्ड वर्कर के लिए। इससे बेरोज़गारी और नौकरी की तलाश में बड़े शहरों में माइग्रेशन कम करने में मदद मिलती है। MSMEs इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में भी मदद करते हैं क्योंकि वे ट्रेड, मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। इससे राज्य की माइनिंग और बड़े इंडस्ट्री पर भारी डिपेंडेंस कम होती है। उद्यम और UAP रजिस्ट्रेशन की बढ़ती संख्या से पता चलता है कि कई MSMEs फॉर्मल बिज़नेस बन रहे हैं, जिससे उन्हें लोन, सरकारी मदद और बेहतर मार्केट के मौके मिलते हैं। हालांकि, झारखंड में MSMEs को अभी भी कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है जैसे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कर की कमी, लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट और छोटे और मीडियम एंटरप्राइज़ की धीमी ग्रोथ। इन समस्याओं को हल करने से MSMEs को तेज़ी से बढ़ने में मदद मिलेगी और झारखंड में संतुलित और टिकाऊ आर्थिक विकास को सपोर्ट मिलेगा।

#### संदर्भ

1. गुप्ता, जे. (2025). *झारखंड में औद्योगिक विकास का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, यूआरजे समीक्षा*।
2. कुमार, डी (2025). रांची में एमएसएमई के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के बीच नौकरी की संतुष्टि का आकलन।
3. पांडे, पी., और चौधरी, ए. (2024). भारत के आर्थिक विकास में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की भूमिका: एक क्रिटिकल एनालिसिस। *भारत के आर्थिक विकास में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज: एक क्रिटिकल एनालिसिस (05 जुलाई, 2024)*।
4. कलईसेलवी, वी., और मैथिली, एम.के. (2024). भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)। *फिजियोथेरेपी के प्रश्न*, 53 (03), 4320-4347.
5. अहमद, एफ., और पात्रा, एम.आर. (2023). एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एमएसएमई की भूमिका। *भारत में एंटरप्रेन्योरशिप-मुद्दे और चुनौतियाँ*, 1 (1), 108।
6. कुमार, जी. (2023). माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और भारत में इनक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़*, 13 (3), 338-343।
7. कडाबा, DMK, ऐथल, PS, और KRS, S. (2022). ग्रामीण और शहरी इलाकों में SMEs/MSE, MSMEs और उससे जुड़े एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने में MUDRA की भूमिका- 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पाने के लिए। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, एंड सोशल साइंसेज (IJMITS)*, 7 (1), 373-389।

8. गुप्ता, आर. (2022). झारखंड के लघु उद्योगों पर कोविड-19 का प्रभाव: एक व्याख्यात्मक विश्लेषण। *इंडियाना जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर*, 3 (8), 23-27.
9. मजीद, एम., खान, जेआई, मुश्ताक, एसओ, और राथर, जेडजी (2021). भारत में एमएसएमई सेक्टर का इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोफाइल। *SEDME (स्मॉल एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन जर्नल)*, 48 (3), 245-256।
10. सरकार, एस (2021). भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में महिलाओं और पिछड़ी जातियों की भागीदारी-एक इंटर-स्टेट असेसमेंट।
11. 11। ग्रांडी, एस. (2019). माइक्रो और स्मॉल बिज़नेस क्लस्टर और लोकल डेवलपमेंट पॉलिसी 1: इंडिया-इटली कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स से मिली जानकारी। *बिज़नेस एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में* (पेज 448-476)। रूटलेज।
12. हुसैन, टी. (2019). भारतीय क्षेत्रों द्वारा लघु और मध्यम उद्यम निर्यात: स्थानिक कारकों की भूमिका का पता लगाना। *मार्केट इंटीग्रेशन की समीक्षा*, 11 (1-2), 7-29।
13. जेना, एनआर, थट्टे, एलआर, और केट, वीजी (2018). भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस: MSME मैनुफैक्चरिंग बिज़नेस फैसिलिटेटर (MSME-MBF) इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। *एकेडमी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नल*, 24 (1), 1-22.
14. रजक, एस.के. (2018). झारखंड में ग्रामीण औद्योगिक विकास। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज*, 5 (4), 613.